'केंद्रीय बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम'

पीएम मोदी ने भारत की अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय नीति पर किया फोकस, परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था हुई मजबूत : राव राजेंद्र सिंह शेखावत

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर भाजपा जयपुर दक्षिण जिला की ओर से प्रबुद्धजन सम्मेलन तथा प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रबुद्धजन सम्मेलन में सांसद मंजू शर्मा और राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने तथा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बजट को सर्व स्पर्शी, सर्व समावेशी बताते हुए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने वाला बताया। इस दौरान विधायक कैलाश वर्मा, जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने भी बजट को लेकर चर्चा की।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। देश के मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के चलते आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े है, और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को

भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे।

साकार करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान के सपने के लिए हर वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया।

सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले किसी ने भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति और भारत की अंतरिक्ष नीति पर काम नहीं किया लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों नीतियों पर कार्य किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

- 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के नेतृत्व में राजस्थान के विकास में देखने को मिली गति'

इससे भारत विकसित देशों के साथ बराबर खड़ा हो पाया है। यह देश के स्वाभिमान और स्वालंबन की परिधी को परिभाषित करता है।

सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने पांव मजबूत किए है। आज भारत नासा की तुलना में कई गुणा कम लागत पर अंतरिक्ष में सेटेलाइट भेज रहा है, ऐसे में विश्व के कई देश हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे है। यह विश्व में हमारे मजबूत अंतरिक्ष नीति को दर्शाता है। इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में अपनी नई पॉलिसी के साथ कार्य कर रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हम विकसित भारत 2047 के सपने का साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास की गति देखने को मिल रही है। भाजपा सरकार का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है, उसकी तुलना में हम 50 फीसदी से ज्यादा पहुंच चुके है और अगले चार साल में इस लक्ष्य को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने प्रदेश की जनता को केंद्रीत करते हुए अपने पिछले दो बजट पेश किए। इसमें किसान की आय बढ़ाने के साथ, आधारभूत व्यवस्था में निवेश, अन्नदाता के खेत से लेकर आमजन के घर तक शुद्ध जल पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए है। भाजपा सरकार ने यमुना, चंबल और साबरमती परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाते हुए विकसित भारत की पृष्टभूमि में विकसित राजस्थान की व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम किया है। कार्यक्रम में जयपुर दक्षिण जिला प्रभारी विमल अग्रवाल, पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, संयोजक हृदय सुमन पारीक भी मंच पर उपस्थित रहे।

आदिवासियों के अलग धर्म कोड पर विधानसभा में नोकझोंक

-विधानसभा संवाददाता-

- जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते वे एसटी आरक्षण, टीएसपी का फायदा छोड़ें : समाराम गरासिया
- बीजेपी विधायक समाराम गरासिया ने सदन में कहा, ''आदिवासी का कोई धर्म कोड नहीं, वह हिंदू है।''

जयपुर। विधानसभा में जनजाति विकास और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान आदिवासियों के अलग धर्म कोड के मुद्दे पर कई बार नोकझोंक और हंगामा हुआ।

गणेश घोघरा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और प्राचीन समय से हिंदू धर्म से जुड़े हैं, रामायण और महाभारत में भी इसके प्रमाण मिल जाएंगे। ज्ञात रहे कि आदिवासी इलाके के कांग्रेस और बीएपी के विधायक अलग आदिवासी धर्म कोड की पहले भी मांग करते आए हैं।

बहस में भाजपा विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि, आदिवासी का कोई धर्म कोड नहीं, वह हिंदू है। अंग्रेज यह सब लाए, आदिवासी गर्व से कहता है कि वह हिंदू है।

उन्होंने कहा- जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते वे एसटी आरक्षण और टीएसपी इलाके का लाभ छोड़ दें। उन्हें दो धर्म का लाभ थोड़े ही मिल सकता है। जो खुद हिंदू नहीं है तो एसटी आरक्षण का फायदा क्यों ले। आदिवासी परंपरागत हिंदू हैं।

उधर कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि, आदिवासियों का अलग से धर्म कोड लागू होना चाहिए। जब बौद्ध, जैन धर्म का अलग से कोड है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं है। आदिवासियों की यह मांग लंबे समय से की जा रही है। आदिवासियों को टीएसपी क्षेत्र में नौकरियों का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है।

हनुमानगढ़ जिले में गोदाम आवंटन में अनियमितता पर की है कार्यवाही : दक

जयपुर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि हनुमानगढ़ जिले में गोदाम निर्माण में पाई गई अनियमितता के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य प्रबंधक, केंद्रीय सहकारी बैंक, हनुमानगढ़ को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई।

दक प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधान कार्यालय स्तर से प्रत्येक जिले में निरीक्षक दलों द्वारा निरीक्षण भी कराया गया। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम आवंटन प्रकिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महती योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जानी है, जिनमें भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं कोटा जिले में उपज के अनुपात में भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम होने से इन जिलों में भण्डारण निर्माण को प्राथमिकता देते हुए श्रीगंगानगर में 17, हनुमानगढ़ में 15 एवं कोटा में 13 गोदाम स्वीकृत किये हैं। परिणामस्वरूप इन जिलों की भण्डारण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

इससे पहले विधायक संजीव कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश की 211 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदान पर गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु कुल 3832 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिए शत प्रतिशत अनुदान के स्थान पर केन्द्र सरकार से लागत के 80 प्रतिशत (अधिकतम रुपए 8 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

आदेश की पालना क्यों नहीं की : अदालत

जयपुर। जयपुर मेट्रो-द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट-एक ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई इकाइयों से निकले अपशिष्टों के जल उपचार व प्रबंधन के लिए बनाए सीईटीपी की निर्माण राशि व इससे जुडी करीब 96 करोड रुपए की वसूली मामले में आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर सहित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे एक मार्च को स्पष्टीकरण देकर यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने 14 फरवरी 2025 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना क्यों की और क्यों ना इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह निर्देश मैसर्स एडवेंट एंवायरकेयर टेक्नोलॉजीज के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अवार्ड होल्डर की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि उन्होंने कोर्ट के सेल अमीन को सहयोग नहीं किया और इसके चलते ही उसने कुर्क वारंट को बिना तामील ही कोर्ट में वापस किया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए वे स्पष्टीकरण दें।

करतारपुरा नाले को पक्का करने और प्रभावित मकानों को तोड़ने का मामला सदन में उठा

- विधायक सराफ ने कहा, ''500 मकानो पर लाल निशान लगाने से लोग दहशत में हैं''
- यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा, ''हाईकोर्ट में रिवाइज्ड योजना पेश करेंगे''

जयपुर। जयपुर के करतारपुरा नाले की चौड़ाई बढ़ाने और उसको पक्का करने के लिए जिन मकानों को तोड़ा जाना है , उसका मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा। मालवीय नगर क्षेत्र से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाते हुए कहा- करतापुरा नाले की चौड़ाई 30 मीटर करने के कारण 500 मकान टूटेंगे। 500 मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं, जिससे लोगों में दहशत है।

सराफ ने कहा कि द्रव्यवती नदी में गिरने वाले नाले का 25 मीटर आउटफॉल है। कच्चे नाले की 30 मीटर चौड़ाई करने का क्या औचित्य है? लोकतंत्र में 500 मकानों को तोड़े जाना संभव नहीं है, किसी हालत में इसे नहीं होने दिया जाएगा। हाईकोर्ट में ये निर्देश नहीं दिए कि नाले की चौड़ाई 30 मीटर की जाए। इसके दोनों तरफ 10-10 मीटर सड़क बनाने का जिक्र है।

मकान तोड़कर सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाना चाहिए। बीजेपी राज में इसके लिए अमृत योजना में 21 करोड़ मंजूर किए थे और मैंने उद्घाटन किया। सरकार बदलने के बाद कांग्रेस राज में यह कहकर इसे बंद कर दिया कि जमीन नहीं है। 30 कॉलोनियों के लोग बदबू से परेशान है, यहां एसटीपी बनना चाहिए।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 2018 में हाईकोर्ट ने नाले को पक्का करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। अब 2018 से लेकर अब तक जो हुआ उस पर कमेंट नहीं करूंगा। इस पर टोकते हुए सराफ ने कहा कि जनता को तब पता लगता है जब लाल निशा लगे।

खर्रा ने कहा कि एक बार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में कार्य योजना पेश कर दी। अब हाईकोर्ट से इसमें संशोधन का आग्रह करेंगे। हाईकोर्ट अनुमति दे देगा तो ऐसी कोई नई कार्ययोजना बनाकर पेश करेंगे, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो।

पेपर खोया तो बिरसा मुंडा पर एक लाइन नहीं बोल पाए मंत्री

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को जनजाति विभाग विकास की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी आदिवासी नायकों के किस्से सुना रहे थे। खराड़ी आदिवासियों के नायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ी यादें पन्नों में देखकर पढ़ रहे थे। खराड़ी ने कहा- बिरसा मुंडा जब रांची में पढ़ने मिशनरी स्कूल में गए तो उनकी चोटी काट दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जुड़ गए और बहुत कम उम्र में रांची जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। इसके बाद खराड़ी रुक गए और पेपर खोजने लग गए, काफी देर खोजने के बाद भी पेपर नहीं मिला तो खराड़ी मुंडा पर कुछ नहीं बोल पाए।

ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर कठोर कार्यवाही

- सहकारिता विभाग ने वर्तमान गठित पैनल से हटाया, भविष्य में पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई

जयपुर। सहकारिता विभाग में ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों को वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल द्वारा इस सम्बन्ध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील अंतर्गत 2जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. 3 जीबी में गबन एवं अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया था। प्रकरण में प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के आदेश पर मुख्य प्रबंधक, जीकेएसबी श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच की गई थी। जांच परिणाम एवं निर्देश में समिति में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक ऑडिट कार्य में उक्त चार्टेड आकाउन्टेंट फर्मों की लापरवाही सामने आई थी। जांच परिणाम के आधार पर कार्यवाही करते हुए मै. विभोर रूपेश एण्ड कम्पनी, मै. रतन गर्ग एण्ड एसोसिएट्स, मै. गोयल नागपाल एण्ड कम्पनी, मै. राकेश लालगढ़िया एण्ड एसोसिएट्स, मै. भरत मून्दड़ा एण्ड कम्पनी एवं देवेन्द्र भटेजा एण्ड कम्पनी को सहकारी सोसायटियों की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है।

राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आज से

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आपर्णो अग्रणी राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान एवं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु आयुष विभाग द्वारा 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला-2025 का आयोजन 1 मार्च से 4 मार्च तक शिल्पग्राम, जवाहर कला केन्द्र में किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए बताया कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेला का उद्देश्य आयुष पद्धितयों की प्रभावशीलता एवं स्वस्थ जीवनशैली के बारे में नागरिकों को जागरूक करना, आयुष विशेषज्ञों के ज्ञान एवं अनुभव का आदान-प्रदान करना तथा रोगों से बचाव व उपचार में इन पद्धितयों की विशेषता से जनमानस को लाभान्वित करना है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेले-2025 का शुभारंभ 1 मार्च को उनके द्वारा किया जायेगा। मेला 4 मार्च तक प्रतिदिन प्रात: 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगा।

मिशन मोड में करें नवीन आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन : गालरिया

- राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 250 वीं बोर्ड बैठक

जयपुर। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं मंडल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 250 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई।

उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर योजना में बन रहे माही अपार्टमेंट सेक्टर-23 में एमआईजी-बी के 143 एवं समृद्धि अपार्टमेंट में एमआईजी-ए के 96 फ्लैटों की स्वीकृत की गई निविदाओं के साथ ही मण्डल की अन्य योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2024-25 की अवधि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 की एवं शेष अवधि 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 की संचालक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। गालरिया ने इस अवसर पर कहा कि मण्डल में चल रही बुधवार निलामी, प्रीमियम सम्पतियों के ऑक्शन तथा विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि आवासन मण्डल आज भी किफायती दरों पर अपने आवास का सपना साकार करने के लिए आमजन की पहली पसंद है और हमें पहली पसंद बने रहने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने अधिकारियों एवं अभियंताओं को आमजन के हितार्थ मिशन मोड में भूमि चिन्हितिकरण कर नवीन आवासीय योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिये।

इस बैठक में सचिव डॉ. अनिल कुमार पालीवाल, मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर, एवं मुख्य सम्पदा प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

अब 10 मार्च तक हो सकेगी मूंगफली खरीद

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। दक ने कहा कि खरीद की अवधि बढ़ाये जाने से पंजीकरण करवा चुके किसान बिना किसी बाधा के अपनी जिन्स का विक्रय कर पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सभी पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

ई.आर.सी.पी. में बांधों को जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

जयपुर। ईआरसीपी में जयपुर ज़िले के बाँधों को जोड़ने को लेकर भारतीय किसान संघ की ज़िला कार्यकारिणी ने शुक्रवार को जयपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जोड़ने की माँग की है।

भारतीय किसान संघ के जयपुर प्रांत सह प्रचार प्रमुख डॉ.लोकेश कुमार चन्देल ने बताया है कि किसान संघ ईआरसीपी में जिन तहसीलों के बाँध नहीं जोड़े गए हैं। उनको जोड़ने के लिए ज़िला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है जिसमें बताया गया है कि बस्सी तहसील के पांटन बांध,दुबली बांध,पृथ्वी पुरा बांध,साँभरिया बांध, देवगाँव बांध, कानोता बांध, नईनाथ बांध, कानोता बांध के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया है। इसी तरह जोबनेर तहसील का कालख बांध,पुनाना झील,डूँगरी बांध,चाकसू तहसील के रामसुंदर बांध, बड़ा तालाब डिक्कियाँ, खेजड़ी बांध,कोटखावदा तहसील से श्यामपुरा बांध,ठीकरियाँ मीणान बांध,दामोदरबांस का बांध,देवसी बांध और आँधी तहसील से रायावाला बांध,खल्ड बांध को जोड़ने की माँग की है। इस दौरान भारतीय किसान संघ के ज़िलाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, ज़िला मंत्री लक्ष्मीनारायण यादव, ज़िला उपाध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा तिलपट्टी, जिला महिला प्रमुख यशोदा मीणा, जैविक प्रमुख कानाराम जाजरवार, जोबनेर तहसील अध्यक्ष मदनपुरी, आमेर अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, चाकसू तहसील अध्यक्षरामोत्तार बलाई, भगवान सहाय प्रेमपुरा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

'बकाया छात्रवृति राशि का भुगतान मार्च तक'

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृति देने हेतु केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की बकाया छात्रवृति राशि का भुगतान मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक किया जायेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक बजट उपलब्धता में कमी होने कारण विगत पांच वर्षों में छात्रवृति का वितरण नहीं हो पाया। इस समयावधि के वित्तीय भार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिख केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि इस छात्रवृति राशि के भुगतान पश्चात केंद्र सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसके उपरांत केंद्र सरकार से शेष रहे विद्यार्थियों की छात्रवृति हेतु भी केन्द्र द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्रदेश में 1731 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दी रीट परीक्षा

रीट की परीक्षा खत्म हुई तो घर लौटने वालों का रैला लग गया। जयपुर जंक्शन पर जान जोखिम में डालकर अभ्यर्थी रेलगाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे।

जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2024 का आयोजन 27-28 फरवरी को सफलता पूर्वक किया गया। परीक्षा दो दिन में तीन पारियों में आयोजित हुई। शुक्रवार को आयोजित परीक्षा में 88.55 प्रतिशत परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही।

परीक्षा के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा की पारदर्शिता एवं परीक्षा की शुचिता के लिए समस्त 1731 परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। रीट कार्यालय में गठित राज्य स्तरीय कमाण्ड सेन्टर एवं जिलों में अभय कमाण्ड सेन्टर से परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई। रीट परीक्षा में नवाचार के तहत डमी परीक्षार्थी एवं अवाछित तत्वों पर नियंत्रण के लिए पहली बार लगभग परीक्षार्थियों के बायोमैट्रिक एवं फेस रिकग्निशन की व्यवस्था की गई। परीक्षा के दौरान सभी जिलों में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। प्रश्न पत्रों को पूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाया गया वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट्स व परीक्षा सामग्री संग्रहण केन्द्रों से रीट कार्यालय में पूर्ण सुरक्षा के साथ प्रेषित की गई। गौरतलब है कि तीन साल बाद रीट की परीक्षा बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न हुई। शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने रीट के निर्विघ्न संचालन पर हर्ष जताया है। शासन सचिव, शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने तीन साल बाद निर्विघ्न रूप से संचालित हुई रीट के लिए सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है।

कुछ लोग राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक टिप्पणी से नहीं चूकते : शेखावत

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है।

शेखावत ने शुक्रवार शाम जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन की हिंदी के विरोध में आई प्रतिक्रिया पर शेखावत ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको पहले हिंदी के विषय में जानना चाहिए। हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। मां भारती के भाल की बिंदी है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उस पर इस तरह की टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों की भावनाओं को उकसाना गलत है।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जिस देश के लोकतंत्र को 75 साल हो गए हों, उस देश में न तो ऐसे विषयों के लिए कोई स्थान होना चाहिए और न ही ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति कोई आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए।